



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227]  
No. 227]

नई दिल्ली, सगलवार, जून 26, 1984/आषाढ़ 5, 1906  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 1984/ASADHA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

निधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1984

सा. का. नि. 475(अ).—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956  
(1956 का 37) की धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रपति  
द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश एतद्वारा प्रकाशित किया  
जाता है, जैसाकि उस उपधारा में अधीन अपेक्षित है —

बम्बई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद में एक स्थायी बेंच की  
स्थापना) आदेश, 1984 ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51  
की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्र-  
पति महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य  
न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद, निम्नलिखित आदेश करते

कीर्ण तथा प्रारम्भ —(1) यह आदेश बम्बई उच्च  
न्यायालय (औरंगाबाद में एक स्थायी बेंच की स्थापना) आदेश,

(2) यह अगस्त, 1984 के 27वें दिन में प्रभावी होगा ।

2 औरंगाबाद में बम्बई उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच की  
स्थापना —

औरंगाबाद में बम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी बेंच  
स्थापित की जाएगी, और औरंगाबाद, बीड, जालना, लटूर  
नांदेड़, औरस्मानाबाद और परभनी जिलों में उत्पन्न होने वाले  
कामों के संबंध में फिलहाल उक्त उच्च न्यायालय में निहित  
कार्यवाहक और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बम्बई उच्च  
न्यायालय के उक्त न्यायाधीश, जिनकी संख्या चार से कम नहीं  
होगी और जिन्हें उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा  
समय-समय पर नामित किया जाएगा औरंगाबाद में बैठेंगे :

परन्तु शर्त यह है कि उक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्याया-  
धीश अपने विवेक से यह आदेश करेगा कि ऐसे किसी जिले  
में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामलों या मामलों की श्रेणी की  
कुलवाई बम्बई में होगी ।

16 जून, 1984

राष्ट्रपति

[एफ सं. 48/10/81-न्याय]

एस. वी. शरण, मंत्रालय सचिव

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COM-  
PANY AFFAIRS**

(Department of Justice)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th June, 1984

G.S.R. 475(E).—The following Order made by the President under sub-section (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956) is hereby published as required by that sub-section :—

**THE HIGH COURT OF BOMBAY (ESTAB-  
LISHMENT OF A PERMANENT BENCH  
AT AURANGABAD) ORDER, 1984**

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), the President, after consultation with the Governor of Maharashtra and the Chief Justice of the High Court of Bombay, is pleased to make the following Order, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the High Court of Bombay (Establishment of a Permanent Bench at Aurangabad) Order, 1984.

(2) It shall come into force on the 27th day of August, 1984.

2. Establishment of a Permanent Bench of the Bombay High Court at Aurangabad.—There shall be established a permanent bench of the High Court of Bombay at Aurangabad, and such Judges of the High Court of Bombay, being not less than four in number, as the Chief Justice of that High Court may, from time to time, nominate, shall sit at Aurangabad in order to exercise the jurisdiction and power for the time being vested in that High Court in respect of cases arising in the districts of Aurangabad, Beed, Jalna, Latur, Nanded, Osmanabad and Parbhani :

Provided that the Chief Justice of that High Court may, in his discretion, order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard at Bombay.

**PRESIDENT**

June 16, 1984

[F. No. 48/10/81Jus.]

S. V. SHARAN, Jt. Secy.